Vol. 253
No. 6

Friday,
5th February, 2021
16 Magha, 1942 (Saka)

PARLIAMENTARY DEBATES

RAJYA SABHA

OFFICIAL REPORT (FLOOR VERSION)
(PART-II)

CONTENTS

Papers Laid on the Table (pages 1 - 4)

Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Social Justice and Empowerment — *Laid on the Table* (page 4)

Leave of Absence - *Granted* (pages 4 - 5)

Statement regarding Government Business (pages 5 - 6)

Motion of Thanks on the President's Address - *Discussion concluded* (pages 6 - 105)

[P.T.O

©
RAJYA SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

PRICE: ₹ 100.00

Special Mention — *Laid on the Table*

Need for giving adequate compensation to farmers whose land is being acquired for Bansagar Irrigation Project (pages 105)

[Answers to Starred and Unstarred Questions (Both in English and Hindi) are available as Part-I to this Debate, published electronically on the Rajya Sabha website under the link https://rajyasabha.nic.in/Debates/OfficialDebatesDateWise]

Website : http://rajyasabha.nic.in
http://parliamentofindia.nic.in
E-mail : rsedit-e@sansad.nic.in

RAJYA SABHA

Friday, the 5th February, 2021/16 Magha, 1942 (Saka)

The House met at nine of the clock,

MR. CHAIRMAN *in the Chair.*

PAPERS LAID ON THE TABLE

Report and Accounts (2019-20) of NRLPS, New Delhi and related papers

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, I, on behalf of Shri Narendra Singh Tomar, lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(a) Annual Report and Accounts of the National Rural Livelihoods Promotion Society (NRLPS), New Delhi, for the year 2019-20, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Society.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 2913/17/2021]

Report and Accounts (2019-20) of MPEDA, Kochi, Kerala and related papers

SHRI V. MURALEEDHARAN: Sir, I, on behalf of Shri Hardeep Singh Puri, lay on the Table, under sub-section (4) of Section 19 of the Marine Products Export Development Authority Act, 1972, a copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(a) Annual Report and Accounts of the Marine Products Export Development Authority (MPEDA), Kochi, Kerala, for the year 2019-20, together with the Auditor's Report on the Account.

(b) Review by Government on the working of the above Authority.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 3167/17/2021]

1. **Report and Accounts (2018-19) of FCI, New Delhi and CWC, New Delhi and related papers**

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जो 29 तारीख को महामहिम के अभिभाषण के समय हुआ, जो 16-17 पार्टियों ने अभिभाषण का बहिष्कार किया, वह बहुत दुखद घटना है। मेरा जितना भी अभी तक संसदीय जीवन रहा है, उसमें मैंने ऐसी घटना नहीं देखी, जब पूरा विपक्ष राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सुनने के लिए नहीं आया। यह काम सरकार के विरोध में नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति का जो संवैधानिक पद है, जो हम लोगों के देश का सर्वश्रेष्ठ पद है, उसका अपमान है। मुझे आश्चर्य हो रहा है और यह हास्यास्पद इसलिए लग रहा है कि भाषण सुनने के लिए तो लोग नहीं आए, लेकिन यहां भाषण देने के लिए सब लोग उपस्थित हो गए हैं, यहां पर अपनी बात कहने के लिए सब लोग उपस्थित हो गए हैं। आप लोग आकर भाषण दे रहे हैं और यही बात मैं कहना चाहता हूं। जो मेरे किसान भाई दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं, मैं उनसे यह बात कहना चाहता हूं कि इन लोगों को आप जरूर पहचानिए। कल मेरे उधर के माननीय सदस्य खड़े होकर बहुत जोर-जोर से भाषण दे रहे थे कि कितना अन्याय हो रहा है। अगर आप किसानों के कष्ट के बारे में जानते तो जानते कि इस सरकार ने किसानों के लिए क्या-क्या किया है, कैसे किसानों की जिंदगी को खुशहाल कर आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि इनको पहचानिए। ये लोग चाहते हैं - कुछ लोग बोल रहे थे कि वे चाहते हैं कि पंजाब में उनकी सरकार आ जाए, कुछ लोग चाहते हैं कि हरियाणा में वे लोग फिर से आ जाएं, इसीलिए वे लोग यहाँ भाषण दे रहे हैं। उनके मन में आपके प्रति कोई संवेदना नहीं है, आपके लिए कुछ नहीं चाहते हैं, वे लोग सिर्फ इसलिए हैं ताकि उनकी सरकार आए। वे सत्ता में आना चाहते हैं। हमारे कई वरिष्ठ नेता चले गए हैं, श्री गुलाम नबी आज़ाद चले गए, आदरणीय दिग्विजय जी हैं, जयराम रमेश जी हैं, मैं और लोगों से भी कहना चाहूंगा, आदरणीय मनोज जी नहीं हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग अपनी पार्टियों का निर्णय लें। आपके जो युवराज हैं, यदि आप उनके कहने पर चलेंगे, तो आपकी पार्टी 415 से 40 पर पहुंच गई है, अगली बार 5 पर पहुंच जाएगी। इसलिए आपके जो वरिष्ठ नेता हैं, आप उनकी बात सुनिए। हमारे नेता ने लगातार किसानों के लिए काम किया है और काम करके दिखाया है। मैं कहना नहीं चाहता था, हमारे आदरणीय मंत्री जी ने सारी बातें कह दी हैं, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन आज आप देश के किसान से पूछेंगे कि आप बिलकुल बात ही नहीं सुन रहे हैं, तानाशाह हो गए हैं, आप किसी की बात नहीं सुनना चाहते, सरकार किसी की बात नहीं सुनना चाहती आदि-आदि। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या तानाशाही यह होती है? आदरणीय जयराम रमेश जी, तानाशाही यह होती है कि जब 1975 में इमरजेंसी लगी थी, तब हमारे पिताजी 19 महीने जेल में थे। तानाशाही वह नहीं थी - वे जेल गए, वह बात दूसरी है, लेकिन 19 महीने हमसे कोई मिलने के लिए नहीं आया। एक आदमी के डर से कोई मिलने नहीं आता था। यह तानाशाही होती है। तानाशाही यह होती है कि हमारे पूर्व प्रधान मंत्री आदरणीय नरसिम्हा राव जी जब पद से हटे तो उनका घर कांग्रेस मुख्यालय से आधा किलोमीटर दूर भी नहीं था, लेकिन उनसे एक भी व्यक्ति मिलने नहीं जाता था। यह तानाशाही होती है, तानाशाही वह नहीं होती है।

कल हमारे एक मित्र खड़े होकर हमारे प्रधान मंत्री जी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे थे कि उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली, उन्होंने यह कर लिया आदि। आपको इससे क्या लेना है? क्या आपके बोलने का यह स्तर है? बंगाल में क्या हो रहा है? आप कह रहे हैं कि हमारी मुख्य मंत्री चप्पल पहनती हैं, तो क्या चप्पल पहनने से कोई महात्मा गाँधी हो जाएगा? महात्मा गाँधी बनने के लिए

परिश्रम करना पड़ेगा, कुरबानी देनी पड़ेगी। मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे प्रधान मंत्री जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों हो रही है? अगर हमारे प्रधान मंत्री जी कुछ कर रहे हैं, तो आप उनके कार्यों को देखिए। प्रधान मंत्री की शक्ल देखने के लिए इस देश ने उनको प्रधान मंत्री नहीं चुना है। उनको चुना गया है और वे देश के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने पूरे विश्व में देश का मान-सम्मान बढ़ाया है, उन्होंने इसलिए काम किया है। मैं आश्चर्यचकित था, हमारे मित्र बोल रहे थे, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं, मैं इस चीज़ को जानना चाहता हूं कि "आयुष्मान भारत" को वहाँ, बंगाल में क्यों नहीं लगाया गया? उसको वहाँ क्यों नहीं लागू किया?

(**उपसभापति महोदय** *पीठासीन हुए*)

मैं इसको जानना चाहूंगा। वे कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पहले से है। बंगाल में उनकी कोई योजना पहले से ही चल रही है। मैं कहूंगा कि आप इसको भी जोड़ लीजिए। आप केंद्र की भी योजना जोड़ लीजिए और वहाँ के लोगों को 5 लाख की जगह 10 लाख रुपये दीजिए। आप यह क्यों नहीं कर सकते हैं? आप यह इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आप प्रधान मंत्री का नाम नहीं जोड़ना चाहते हैं। हमारे प्रधान मंत्री जी का तो यह स्वभाव है कि वे अपना नाम नहीं जोड़ते हैं। सारी योजनाएं प्रधान मंत्री से हैं, जैसे "प्रधान मंत्री सम्मान निधि" आदि। पहले तो नाम जोड़ा जाता था कि इस प्रधान मंत्री की योजना है। आज यह प्रधान मंत्री है, कल कोई और होगा, तो वह उस प्रधान मंत्री की योजना है। इसलिए मैं चाहूंगा, मैं बंगाल के अपने साथियों से कहूंगा, मैं बंगाल के लोगों से अपील करूंगा कि आप इस बात को जानिए कि कौन सी सरकार आपके लिए काम करेगी, आपके विकास के लिए काम करेगी, आपके सम्मान के लिए काम करेगी।

महोदय, मैं एक चीज़ कहना चाहता था। मेरे पास समय कम है, लेकिन जो धारा 370 हटी है, मैं उसके बारे में जरूर कहना चाहूंगा। मेरा मानना है कि पिछले कई सालों में यह सबसे अच्छा काम हुआ है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं - हो सकता है कि व्यक्तिगत रूप से यह मेरा मन है, क्योंकि उसके पहले हम जब भी भाषण देते थे, तो हमें बार-बार यह बात दोहरानी पड़ती थी कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इसका क्या मतलब है? वह पहले भी अभिन्न अंग था, आज भी है, लेकिन हम लोग पहले ऐसा बोलते थे, क्योंकि हमारे मन में कहीं कोई शंका थी कि वह हमारा अंग नहीं है, परंतु अब धारा 370 हटने के बाद लोगों ने लगातार यह बात कहनी बंद कर दी है। यह बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं पता है कि आप लोग क्या सोचते हैं, लेकिन जो आम आदमी है, वह इस बात से जुड़ा हुआ है। उसे लगता है कि हाँ, कश्मीर अब हमारा एक अभिन्न अंग है और हमारे साथ है। आदरणीय गुलाम नबी जी कह रहे थे कि उसे Union Territory क्यों बना दिया गया। मैं चाहूंगा कि हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, ये बताएं उनको। लेकिन क्या आपने लद्दाख के लोगों के बारे में सुना है? आप उनके बारे में सोचिए। लद्दाख के लोग Union Territory बनने के बाद बहुत खुश हैं। वहाँ अच्छे काम हो रहे हैं, वहाँ विकास के काम हो रहे हैं। भारत सरकार की सारी योजनाएँ, जो वहाँ पर लागू नहीं थीं, आज वहाँ पर लागू हैं। वहाँ घर बन रहे हैं, वहाँ सड़कें बन रही हैं। पिछले एक साल में जो काम हुआ है, उससे वहाँ के लोगों का जो विकास हो रहा है, जो जीवन स्तर बढ़ रहा है, आप वह देखिए। सर, शायद मेरे पास अभी और समय है।

श्री उपसभापति : आप बोलिए और conclude कीजिए।

श्री नीरज शेखर : मैं जल जीवन योजना के बारे में, जो माननीय प्रधान मंत्री जी ने शुरू की है, उसके बारे में कहना चाहूँगा। यह मेरे लिए और हम जिस क्षेत्र से आते हैं, बलिया और जो गंगा के किनारे का इलाका है, जहाँ पर आर्सेनिक पानी की बहुत बड़ी समस्या है, प्रधान मंत्री जी की यह जो योजना है कि 2024 तक हर घर तक नल से पानी पहुँचाएँगे, यह बहुत महत्वपूर्ण योजना है। मेरा यह मानना है कि पिछले 70-72 साल में हम लोग अपने लोगों को पीने का स्वच्छ पानी नहीं दे पाए हैं। यह कमी हम लोगों में है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ। जब मैं उन बच्चों को देखता हूँ, जो आर्सेनिक पानी पीकर आज विकलांग हैं, जिनकी आँखों की रोशनी चली गई है, तो मुझे बहुत कष्ट होता है। माननीय प्रधान मंत्री जी यह जो काम कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इसमें उनका सहयोग करें। मुझे लगता है कि यह एक बहुत बड़ी योजना है। अगर यह 2024 तक पूरी होती है, तो यह देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योजना होगी।

मैं फिर से एक बात दोहराना चाहूँगा। यह शौचालय वाला विषय है। मैं बार-बार यह कहता था, जब मैं विपक्ष में था, तब भी मैं यह बात कहता था कि प्रधान मंत्री जी की यह जो शौचालय की योजना है, यह सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छी योजना है।

श्री उपसभापति : माननीय नीरज जी, कृपया conclude करिए।

श्री नीरज शेखर : सर, क्या 12 मिनट हो गए?

श्री उपसभापति : लगभग होने वाले हैं ।

श्री नीरज शेखर : मैं यह कहना चाहता हूँ कि शौचालय की जो योजना है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। यह हमारे सम्मान से जुड़ी हुई है। पता नहीं कितने लोग गाँवों में जाते हैं या नहीं जाते हैं, लेकिन जब मैं आज से 7-8 साल पहले वहाँ जाता था और जब सड़कों के किनारे का दृश्य देखता था, तो उससे शर्मनाक कोई दृश्य नहीं होता था। मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे शौचालय बन रहे हैं और आगे भी यह काम होता रहेगा।

अंत में मैं फिर से एक बात कह कर अपनी बात खत्म करूँगा। जो किसान वहाँ बैठे हुए हैं और जिनको आपत्ति है, प्रधान मंत्री जी के मन में यह है कि यह समस्या दूर होनी चाहिए। प्रधान मंत्री जी ने बार-बार कहा है और मेरी समझ में नहीं आता है कि हर चीज़ का मज़ाक क्यों उड़ाया जाता है, प्रधान मंत्री जी ने कहा कि मैं एक कॉल दूर हूँ, उसका यह मतलब नहीं है कि आप मुझे फोन करिए। प्रधान मंत्री जी का यह मतलब है कि प्रधान मंत्री जी बात करने के लिए हमेशा तैयार हैं और अगर एक भी किसान दुखी होता है, तो प्रधान मंत्री जी को कष्ट होता है। इसलिए प्रधान मंत्री जी यह बात कह रहे हैं। कुछ लोग वाह-वाह कर रहे हैं, मैं यह कहना चाहता हूँ कि कम से कम मैं अपने बड़े अनुभवी व्यक्ति की बात पर वाह-वाह कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग, जिनको कोई अनुभव नहीं है, जो काम करना नहीं जानते, उनकी बातों पर भी वाह-वाह करते हैं। इसलिए

वे ध्यान रखें कि ऐसी बातों पर वाह-वाह न करें, जिससे देश का नुकसान हो। ऐसा हो रहा है, आपकी पार्टी का भी नुकसान हो रहा है और देश का भी नुकसान हो रहा है। आप इसको समझें।

मैं फिर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।

SHRI SUBHAS CHANDRA BOSE PILLI (Andhra Pradesh): Thank you very much, Mr. Deputy Chairman, Sir, for giving me this opportunity to speak on the Motion of Thanks on President's Address. *"Sir, because of Covid-19, people from all walks of life have suffered throughout the country and the world too. There wasn't a single family which was not affected by this pandemic. Be it the landless or the landlords, everyone was affected. Some families experienced financial loss, some experienced loss of life and some experienced both. We expected that some relief to the unorganized sector like agriculture labour will be mentioned in the President's Address. It is very unfortunate that there was not a single mention of it in the entire President's Address. In our country, nearly fifty crore people fall under this category of unorganized sector. During lockdown, their condition became very miserable; they could not have proper meals as they could not go out for work. It is the State Governments that had come to their rescue during that period. It is very unfortunate that in the entire Address by the President, there was not a single mention of the miserable condition faced by these people and the help extended by the State Governments.

Sir, I would like to give an analogy on the conditions of the people of Andhra Pradesh with a song from a Telugu movie.

"*Sailing in the rain water and winds*

Don't know where the coast is and the destination."

This is a song from a Telugu movie. Due to Covid-19, situation of the poor in our country became as good as has been described in this song. Sir, when the poor are experiencing such miserable condition, I do not hesitate to say, it is the responsibility of the Central Government to take care of them; not only helping the poor, it is also the responsibility of the Central Government to make the State Governments self-reliant to help the poor. Sir, please consider this matter.

Eminent scientist Einstein had once said, "Knowledge of what is does not open the door directly to what should be." It means, it is natural to have problems but when problems occur and if it happens for the family, it is the responsibility of the head of the family to solve the problem. In the same way, if the problem persists with the State and the Centre, the responsibility lies with the heads of the State i.e. Chief

* English translation of the original speech made in Telugu.

Ministers and the Prime Minister respectively. Sir, here I would like to mention that the heads of the families and the Chief Ministers have fulfilled their responsibilities during the pandemic. But, the Central Government has failed in giving assurance to the people for the betterment of their living and financial conditions.

Sir, you are aware, President's Address is nothing but the policy document of the Government. The policy document reflects the way of the administration for the financial year. While presenting the policy document, if there is no mention about the Government's plans in safeguarding the interests and the livelihood of the poor, how can one keep trust in democracy? Sir, through you, I request the Central Government to give a serious thought to this.

As per the statistics provided by the Government of India, the Reserve Bank of India, the World Bank, CRISIL and the State Bank of India, the fact emerged that there has been a constant decline in the GDP of our country and it further reduced because of Covid-19 resulting in loss of employment. Sir, I request you to study 'Shrunk by the Pandemic', a report by G-7 countries. In this report, India stands second after America in GDP loss. Brazil occupies third position. China is in a better position with 3.3 percent. Apart from China, economy has been severely hit in other countries.

Sir, I would like to quote a verse by Shri Gurajada Apparao.

It means, "Country is not just mud and soil, Country means people. Stop shallow talk, think of strong help." In the recent past, this verse was referred to by our Hon'ble Prime Minister on a few occasions.

Under the present circumstances, the Central Government's major responsibility is not to leave the States to their fate but to acknowledge the financial problems of the States and sanction the grants to the respective States without any cut in grants. However, there was no mention of this in the President's Address. The Governor of Reserve Bank of India recently asked the people of the country not to worry as we have two major ammunitions with us for solving the financial problems of the countrymen and the States. We will use them when required. What are those weapons? Why haven't they used the weapons till now? Does he think that the right time has not yet come? Or is it, though the time has come, Hon. Prime Minister has not given his approval to it? We would have been little happier if the details of these two weapons were disclosed in the President's Address. I request you to make amendments, at least now, to the President's Address and help the poor, especially the labourers from the unorganized sectors. The responsibility of the Central Government is to help the States, only then it will serve the purpose of what our Hon. Prime Minister said "Jaan bhi, Jahaan bhi." There is no use giving sermons. If we do

not strive for the betterment of the living conditions of the people, they will lose trust in democracy and in the elected representatives.

I will mention one or two incidents as examples to describe the functioning of the Governments these days. People of Andhra Pradesh have a long-cherished dream. Their dream is Special Category Status to the State of Andhra Pradesh. When Andhra Pradesh State Re-organization Bill was being passed in the Parliament, Special Category Status to the State was promised to the people of Andhra Pradesh. The then Hon. Prime Minister, Dr. Manmohan Singh promised Special Category Status to the State of Andhra Pradesh with Parliament being a witness to it. Sir, he promised Special Category Status to Andhra Pradesh stating that Andhra Pradesh is a newly formed State and has no Capital of its own. The State is also devoid of good hospitals and Universities and suffers from highest revenue deficit. He said that all the said problems would be solved by granting Special Category Status to the State. He totally forgot it and there was not a single effort from him for implementation of Special Category Status to the State.

Shri Marri Chenna Reddy, former Chief Minister of Andhra Pradesh has once said, "The word delivered from the mouth of the Hon. Chief Minister is a G.O.". Those days should come back. When the Prime Minister makes a promise in Parliament, we consider it as an Act but never did we imagine that the successive Prime Ministers will keep it aside. If such incidents happen, people will lose trust in democracy and democratically elected representatives. Sir, through you, I request the Hon. Prime Minister to give it a thought.

Sir, the Government of Andhra Pradesh and the Chief Minister of Andhra Pradesh are being blamed regarding non-implementation of Special Category Status to the State of Andhra Pradesh. If we analyze as to whose mistake it is, is it the mistake of the TDP leaders who were in power for five years before our Government and failed to get Special Category Status to the State by pressurizing the Central Government? Is it the mistake of the Hon. Prime Minister for not fulfilling the promise made by the former Prime Minister? Or is it the mistake of our Chief Minister? Sir, yesterday they have spoken in this House and tried blaming our Chief Minister. I ask them, have you ever tried, at least for one single day, for getting Special Category Status to the State?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI SUBHAS CHANDRA BOSE PILLI: Five more minutes. Sir, you allotted ten minutes for a Party with only one Member. My Party's strength is six and you should

allot at least twenty minutes. Sir, Telugu Desam Party leaders are claiming that nearly seventy three percent of work with respect to Polavaram Project was carried out during their tenure and now the works have come to standstill. This is factual error. TDP representatives always give wrong details outside this august House. Who will be the loser if they give wrong details during the debate and submit the reports with factual errors? Andhra Pradesh will be the loser here. So, I request you not to consider their reports submitted with factual errors.

Sir, as the works are being carried out in full swing to complete the Polavaram Project by April 2022, I request the Central Government to release the already allotted funds and sanction the revised estimate for the project and also make a statement regarding this.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI SUBHAS CHANDRA BOSE PILLI: Sir, one more minute. In recent times, the major sensitive elements with regard to politics in our country are community, region and religion.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude or I will call the other speaker.

SHRI SUBHAS CHANDRA BOSE PILLI: Sir, one last minute please. These days, TDP, the opposition party in Andhra Pradesh is concentrating on Gods. They are attacking the temples. During their tenure, a total of 859 attacks on temples have taken place with 163 attacks in 2015, 207 attacks in 2016, 189 attacks in 2017, 123 attacks in 2018 and 141 attacks in 2019. This is their background and now they are trying to blame our Government. This is totally unacceptable. Sir, in this august House, if any Member has to blame other Members or State Governments, it should be done with proper proof. We are extremely disappointed because they are indulging in mudslinging on us without any proof. I have many issues to raise and debate but considering the paucity of time, I will conclude now and will raise the issues during the debate on Budget. I once again thank you for giving me the opportunity to participate in the debate." Thank you, Sir.

श्रीमती इंदु बाला गोस्वामी (हिमाचल प्रदेश): उपसभापति जी, 29 जनवरी, 2021 को राष्ट्रपति जी के द्वारा दोनों सदनों को सम्बोधित करने के लिए हम उनके आभारी हैं। मैं संसद के उच्च सदन में प्रथम बार सदस्य के रूप में चुन कर आयी हूँ, मेरा सदन में बोलने का पहला मौका है। इसके लिए मैं अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद करती हूँ। साथ ही अगर मुझसे बोलते हुए

कोई भूल-चूक हो जाए, तो मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगी। उपसभापति जी, मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का मौका देने के लिए मैं आपका भी आभार व्यक्त करती हूँ।

उपसभापति जी, मुझे आज वह दिन याद आ रहा है, जब इसी सदन में 11 जून, 2014 को हमारी नेता और मार्गदर्शिका स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की आभा निराली है। मैं आज उन्हीं के शब्दों को दोहराना चाहती हूँ। राष्ट्रपति जी का अभी का अभिभाषण भी निराला है, क्योंकि संसद का सत्र अलग परिस्थितियों और अलग व्यवस्थाओं में हो रहा है। नये साल में हम प्रवेश कर गये हैं, हम देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने वाले हैं और साथ ही साथ हम कोरोना जैसी भयंकर महामारी से भी सफलतापूर्वक पार पाने में काफी हद तक सफल हो चुके हैं। इन 75 वर्षों में देश की शासन व सत्ता की यात्रा क्या रही, कितने समय तक देश में हमारी सरकार रही और हमारी सरकार तथा दूसरी सरकारों के कार्यों में क्या अंतर रहा, जिन्होंने अधिक समय तक इस देश में शासन सत्ता का भरपूर आनन्द उठाया, उनके क्रियाकलापों और देश के प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के 6 साल के कार्यकाल में क्या गुणात्मक परिवर्तन हुए - इस पर सटीक विश्लेषण मन से मतभेद मिटाते हुए होना चाहिए। जब हम सरकार के 6 वर्ष के कार्यकाल की बात करते हैं, उसके विश्लेषण की बात करते हैं, तो समझ में नहीं आता कि सरकार की 6 साल की उपलब्धियों को कहाँ से शुरू करें।

महोदय, हमारी सरकार ने प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से कोरोना जैसी भयंकर महामारी से देश की 130 करोड़ आबादी को बचाया, उसके लिए मैं विशेष रूप से देश के लोकप्रिय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगी। प्रधान मंत्री जी ने न केवल सरकार, बल्कि देश की जनता को भी इस लड़ाई से लड़ने के लिए बराबर का भागीदार बनाया - ताली बजा कर, थाली बजा कर, दीये जला कर। जनता की आवाज़ बन कर, देश की जनता के साथ सीधा संवाद करके देश की जनता को इस बात का एहसास दिलाया कि आपका प्रधान सेवक और उसकी पूरी सरकार इस भयंकर विपदा में आपके साथ खड़ी है, लेकिन विपक्ष को इसमें भी कहीं न कहीं बुराई नज़र आती है। प्रधान मंत्री जी के सीधे संवाद और दिशा-निर्देशों को देश की जनता ने माना। यह केवल और केवल इसलिए संभव हो सका, क्योंकि देश को अपने प्रधान मंत्री की हर कही गई बात पर विश्वास है। देश की जनता को विश्वास है कि हमारा प्रधान मंत्री जो कहता है, उसको अमलीजामा भी पहनाता है। बूढ़े, जवान, बच्चे, हर किसी की ज़ुबान पर आज एक ही बात है कि अगर श्री नरेन्द्र मोदी जी देश के प्रधान मंत्री न होते, तो हमारे देश का भी वही हश्र होता, जो विश्व की बड़ी-बड़ी शक्तियों का हुआ। प्रधान मंत्री जी ने सही समय पर लॉकडाउन लगा कर अपने देश को बचा लिया। जब पूरी दुनिया और दुनिया के बड़े-बड़े देश, जिनकी स्वास्थ्य सुविधाएँ बेहद विकसित होते हुए भी कोरोना से हताश और निराश थे, उस समय हमारे पास न कोरोना मेडिकेटेड हॉस्पिटल्स थे, न पीपीई किट्स थीं, न वेंटिलेटर्स थे, टैस्टिंग कैपेसिटी भी न के बराबर थी, तब इस परिस्थिति में हमारे प्रधान मंत्री जी लॉकडाउन लगा कर बैठ नहीं गए, बल्कि उन्होंने देश की जनता को कोरोना से लड़ने के लिए तैयार किया। आज हमारे पास 1,600 कोरोना मेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं, 40 लाख से ज्यादा मेडिकेटेड बेड्स हैं। उस दिन हमारी जो टैस्टिंग कैपेसिटी 1,500 प्रतिदिन थी, वह आज 15 लाख प्रतिदिन है। उस समय हम

एक भी पीपीई किट नहीं बनाते थे, आज हमारी सरकार साढ़े चार लाख पीपीई किट्स बना कर दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर रही है।

महोदय, देश की जनता प्रधान मंत्री और उनकी सरकार की नीतियों और अपने देश के उन वैज्ञानिकों को साधुवाद दे रही है, जिनकी कुशलता व मेहनत से हम देश में सस्ती और कारगर वैक्सीन बनाने में सफल हुए। भारत सिर्फ 15 दिनों में अपने 30 लाख से ज्यादा corona warriors का टीकाकरण कर चुका है, जबकि अमेरिका जैसे समृद्ध देश को इसी काम में 18 दिन लगे थे और ब्रिटेन को 36 दिन लगे थे।

हम हेल्थ सेक्टर में कहाँ थे और अब कहाँ हैं? क्या यह देश के प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी व उनकी सरकार के कार्यों का उल्लेख करने के लिए काफी नहीं है? जो कई सालों से असंभव था, वह हमारी सरकार ने 6 साल में संभव करके दिखाया, इसलिए आज ग्लोबल रेटिंग के मुताबिक प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी एक ऐसे नेता हैं, जो कोरोना महामारी के दौरान भी ग्लोबली नंबर वन हैं। क्या इसकी प्रशंसा नहीं नहीं होनी चाहिए? अगर विश्व प्रधान मंत्री जी का लोहा मानता है, तो हम और आप क्यों नहीं? लेकिन विपक्ष को तो सत्ता सुख सता रहा है, इसलिए उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ प्रधान मंत्री जी का विरोध करना आता है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. इंदु बाला जी, कंक्लूड करें।

श्रीमती इंदु बाला गोस्वामी : उपसभापतिजी, मैं विशेष रूप से महिला शक्ति की ओर से अपने देश के प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने प्रधान मंत्री जी के हर आदेश को, हर संदेश को अपने में आत्मसात किया। जिस तरह से कोरोना काल में महिलाओं ने पूरे देश में मास्क्स बनाकर लोगों की सहायता की, उसके लिए मैं विशेष रूप से प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन समय कम होने के कारण मैं पुनः यह प्रस्ताव, जिसे भुबनेश्वर कालिता जी ने रखा है, उसका समर्थन करती हूँ।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले): डिप्टी चेयरमैन सर, इस सभागृह में माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। आपने सभी पार्टी के लोगों को बोलने का मौका दे दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जो मेरी Republican Party of India है, इस पार्टी की स्थापना डा. बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने की थी। डा. बाबा साहेब अम्बेडकर जी चाहते थे कि अपने देश में टू पार्टी सिस्टम होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने राममनोहर लोहिया जी को भी एक पत्र लिखा था। उसके पहले All India Scheduled Castes Federation पार्टी थी। बाबा साहेब अम्बेडकर जी सन् 1952 में मुंबई से लोकसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन वे हार गए थे। मैं भी उसी पार्टी से आता हूँ।

मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार के सर्वांगीण विकास की दिशा दिखाने वाला अभिभाषण है। यह अभिभाषण नेशन को मजबूत करने वाला है। जो दलित हैं, आदिवासी हैं, ओबीसी हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, खेत-मजदूर हैं, कामगार हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, बेरोजगार हैं, यह अभिभाषण ऐसे सभी लोगों को न्याय की दिशा

दिखाने वाला है, इसीलिए इस अभिभाषण का स्वागत करने के लिए, इसका सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ।

मैंने यह माँग भी की थी कि वर्ष 2021 में जो जनगणना हो रही है, वह जनगणना जाति के आधार पर होनी चाहिए, ताकि हर जाति का परसेंटेज कितना है, इसकी जानकारी मिल सके।

अपनी पार्टी की तरफ से मेरी यह भी माँग है कि महाराष्ट्र में मराठा समाज आरक्षण माँग रहा है, हरियाणा में जाट समाज आरक्षण माँग रहा है, राजस्थान में राजपूत समाज आरक्षण माँग रहा है, उत्तर प्रदेश में ठाकुर समाज आरक्षण माँग रहा है, इसी तरह से क्षत्रिय समाज की एक बहुत बड़ी पॉप्युलेशन भी अपने देश में है, तो जिस तरह से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दस प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय माननीय प्रधान मंत्री जी ने ले लिया है...

श्री उपसभापति : अठावले जी, कृपया कक्लूड करिए।

श्री रामदास अठावले : अभी तो एक मिनट भी नहीं हुआ है।

श्री उपसभापति : आपका नाम माननीय चेयरमैन साहब ने पुकारा था, लेकिन आप उस वक्त नहीं थे। अब समय कम हो गया है प्लीज़।

श्री रामदास अठावले : मैं सुबह 11 बजे से यहीं बैठा हूँ।

महोदय, इसलिए मेरी माँग है कि जो क्षत्रिय समाज है, उन्हें अलग से आरक्षण देना चाहिए। इसी तरह से Scheduled Castes और Scheduled Tribes को promotion में रिज़र्वेशन देने के संबंध में भी विचार होना चाहिए।

इसके साथ-साथ, अभी जो किसान कानून आए हैं, उन किसान कानूनों के संबंध में मेरा कहना यह है कि नरेन्द्र मोदी जी किसानों के वोटों की वजह से दूसरी बार सत्ता में आए हैं, तो वे नरेन्द्र मोदी जी किसानों के खिलाफ कानून क्यों लाएंगे? इन कानूनों के बारे में सभी लोग बोल रहे हैं कि ये काले कानून हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि,

"जो बोलते हैं कि यह कानून है काला,
उनके मुंह पर लगाना है क्या ताला।"

मेरे कहने का मतलब है कि यह कानून इतना अच्छा है, इस कानून का समर्थन होना चाहिए था। हममें आंदोलन करने वाले किसानों के लिए बहुत आदर है, लेकिन इतने दिन आंदोलन नहीं करना चाहिए। हमने भी आंदोलन किए हैं। हम भी आंदोलन करते-करते ही इधर तक आए हैं। किसानों को इतने दिनों से तकलीफ हो रही है।

श्री उपसभापति : अठावले जी, प्लीज़ कक्लूड करें।

श्री रामदास अठावले : जिन 170-80 किसानों की मृत्यु हुई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मुझे लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर stay दे दिया है, तो फिर आंदोलन की क्या आवश्यकता

है, आंदोलन पीछे लेने की आवश्यकता थी। सरकार ने भी बोला है कि सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगा, वह हमें मंजूर है। माननीय प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी बार-बार बोल रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : हम दूसरे स्पीकर को बुला रहे हैं। अठावले जी, अपने पास समय कम है। ...(**व्यवधान**)...

श्री रामदास अठावले : इसलिए मुझे लगता है कि इस कानून के संबंध में हमें पॉज़िटिव विचार होना चाहिए। ...(**व्यवधान**)... इसको बदलने के लिए हम लोग तैयार हैं। ...(**व्यवधान**)... इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपने दो शब्द खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत।

श्री उपसभापति : धन्यवाद। अब, डा. अनिल जैन।

डा. अनिल जैन (उत्तर प्रदेश)**:** उपसभापति महोदय, आपने मुझे माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

माननीय राष्ट्रपति जी ने देश में उत्साह और ऊर्जा का संचार किया, जब उन्होंने अपने अभिभाषण में माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार की 6 साल की उपलब्धियों का ज़िक्र किया। लेकिन दुर्भाग्य रहा, लोकतंत्र में इस तरह की घटनाएँ नहीं होनी चाहिए। जिन्होंने देश पर लम्बे समय तक राज किया हो, वे पार्टियाँ राष्ट्रपति के अभिभाषण का भी बहिष्कार करें, यह कतई अलोकतांत्रिक है, अशोभनीय है, दु:ख का विषय है।

माननीय उपसभापति महोदय, नेतृत्व की क्षमता क्या है? Easy going way में तो सब लोग चला लेते हैं, लेकिन नेतृत्व की कसौटी की पहचान चुनौती के समय होती है। इस देश में किसी भी प्रकार की चुनौती हो, चाहे एलओसी पर चुनौती आई हो, तब सर्जिकल स्ट्राइक करके, एयर स्ट्राइक करके देश का मान-सम्मान बढ़ाने का काम किया गया, तो वह नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में किया गया। उस समय भी लोगों ने सवाल उठाए, उसको भी minimize करने की कोशिश की। जिसका मान-सम्मान सारी दुनिया में बढ़ा, हमारी सेना के रण-बाँकुरों का सम्मान बढ़ा, उसको भी minimize करने की कोशिश की गई। चाहे चुनौती एलएसी पर आई हो, गल्वान घाटी में आई हो, तब देश के प्रधान मंत्री ने लद्दाख में जाकर, सैनिकों के बीच में जाकर उनकी हौसला अफज़ाई की है। देश के जिन सैनिकों ने देश के ऊपर अपना बलिदान दिया है, उनकी हौसला अफज़ाई की है, उनका मान-सम्मान बढ़ाने का काम किया है। उस समय भी कुछ लोग चीन के साथ hobnobbing करते थे, उनके राजदूत से चर्चा-वार्ता करते थे। किसलिए, देश का मान-सम्मान गिराने के लिए? एक तरफ यह नेतृत्व है कि किसी भी चुनौती में देश का मान-सम्मान, स्वाभिमान बढ़े, इसकी चिन्ता करता है। यह नेतृत्व है। नेतृत्व की कसौटी चुनौती के समय पहचानी जाती है। देश के करोड़ों-करोड़ लोगों के जीवन में, शोषित, पीड़ित, वंचित, गाँव, गरीब, किसान, मज़दूर, इनके जीवन में उत्थान आए, इनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो, incremental नहीं, transformational परिवर्तन हो, अगर इसकी चिन्ता करने की बात आती है, तब नरेन्द्र मोदी जी ने इस देश में 135 योजनाओं में से 90 प्रतिशत योजनाएँ किसानों को समर्पित कीं। 13 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा डीबीटी के माध्यम से सीधे इस देश के गाँव, गरीब, किसान,

श्री उपसभापति : अब आपकी बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है,सिर्फ बृजलाल जी की बात रिकॉर्ड पर जा रही है। मैं बृजलाल जी से कहता हूं कि आप अपनी बात शुरु करें।

डा. अनिल जैन : *

श्री बृजलाल: उपसभापति महोदय, ...(**व्यवधान**)...

डा. अनिल जैन : *

श्री उपसभापति : अब आपकी बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है, सिर्फ बृजलाल जी की बात रिकॉर्ड पर जा रही है। प्लीज़, प्लीज़।

डा. अनिल जैन : *

श्री बृजलाल (उत्तर प्रदेश)**:** सभापति महोदय, आज मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया गया है, जिसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। महोदय, मेरी पृष्ठभूमि एक IPS अधिकारी की रही है और मैंने साढ़े सैंतीस वर्ष तक वर्दी पहनी है। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि देश में प्रगति तब होती है जब कानून व्यवस्था चाक-चौबंद रहती है। जब व्यापारी, किसान, उद्योगपति बिना भय के freely काम करता है, तब इस देश की प्रगति होती है। इसके साथ ही साथ जो फॉरेन निवेश है, FDI है, वह देश में आता है।

महोदय, मैंने देश की इतनी लम्बी सर्विस में आतंकवाद भी देखा है, naxalism भी देखा है, बड़ी कानून व्यवस्था भी देखी है। जो हमारे तरीके हैं, हमने उनसे कानून व्यवस्था को, terrorism को, naxalism को निपटाया है। मुझे नॉर्थ-ईस्ट का भी अनुभव रहा है। मैं करीब 37 वर्ष पहले इन्हीं दिनों में असम में NEFA border पर तैनात था। मैं लोअर असम में भी था और मैंने असम की वह हालत भी देखी है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय असम में क्या स्थिति है? आज वहां पर अमन-चैन हुआ है और इसमें और भी प्रगति हो रही है। यह परिणाम सुशासन का है, good governance का है।

महोदय, समय कम है, इसलिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जो कानून व्यवस्था है, हम उससे अपने-अपने तरीके से निपट लें, लेकिन जब राजनीतिक पार्टियां भोले-भाले लोगों को गुमराह करती हैं तब बड़ी प्रॉब्लम होती है और वह बड़ा दुखद होता है। महोदय, मैं अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखता हूं। बीजेपी की सरकार दिनांक 01.01.2016 को एक Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Act लाई थी। महोदय, जहां पर पहले 22 अपराध होते थे, उनमें 25 और जोड़े हैं। पहले साउथ में देवदासी प्रथा थी, उसको खत्म किया है। पहले लोगों के बारात निकालने पर अवरोध करते थे। कभी आगरा में दंगे हुए हैं, मैं भी आगरा का SSP रहा हूं और उस समय माननीय Secretary General साहब वहां के

---

* Not recorded.

DM रहे हैं। ऐसा उस समय वहां का इतिहास रहा है, उसको Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Act में लाकर के प्रधान मंत्री मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया है। पंचायतों में, रिजर्वेशन में दलित आते हैं, लेकिन उनको कभी काम नहीं दिया जाता। उन पर अवरोध उत्पन्न किया जाता है। महोदय, इसको भी मोदी जी दिनांक 01.01.2016 को Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Act में लाए थे। महोदय, अगर कहीं अपराध हो जाए, तो SC/ST Rules के अंतर्गत अनुदान दिया जाता है। इस सरकार ने उसको चार गुना से ज्यादा बढ़ाया है। महोदय, यदि किसी एससी/एसटी की मृत्यु हो जाती है, मर्डर हो जाता है, तो उसकी विधवा को एससी/एसटी एक्ट के तहत आजीवन पांच हज़ार रुपये महीना पेंशन with dearness allowance मिलती है, बच्चों को ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा मिलती है। यदि उनके पास मकान नहीं है, तो मकान की सुविधा और बाकी सुविधाएं भी बीजेपी गवर्नमेंट ने दी हैं। महोदय, दो साल पहले सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी। उसके बाद कुछ पार्टीज़ ने ऐसा गुमराह किया कि जैसे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग न हो। सुप्रीम कोर्ट हमारा शीर्षस्थ कोर्ट है। उसके बारे में ऐसा माहौल पैदा किया, जैसे कि यह माननीय मोदी जी ने किया हो। कुछ पार्टीज़ ऐसी थीं, जो दलितों की मसीहा बनती हैं। मैंने उस गवर्नमेंट में भी काम किया है। 19 मई, 2007 को एक आदेश हुआ था, जो दलितों की मसीहा कहलाने वाली सरकार थी, कि murder, attempt to murder और बलात्कार, इन तीनों को छोड़कर दलितों के मुकदमें में एससी/एसटी एक्ट न लगाया जाए। यह रिकॉर्ड पर है। जिन्होंने dilute किया, वे उस समय कानून व्यवस्था की समस्याएं खड़ी कर रहे थे। महोदय, मैं माननीय मोदी जी का शुक्रगुज़ार हूं कि इन्होंने Constitution Amendment लाकर इसको form में लाए।

उपसभापति महोदय, मैं CAA पर आता हूं। CAA के genesis में बताना चाहता हूं। जोगेन्द्र नाथ मंडल जी बंगाल के नेता थे, बाबा साहेब के सहयोगी थे और जब देश का बंटवारा हुआ, तब बाबा साहेब ने कहा कि मंडल साहब, आप चले आइए। वे नहीं माने। उन्होंने जिन्ना का साथ दिया। वे पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर बने। वे लॉ मिनिस्टर तो बने, लेकिन उन्हीं की कौम के लोगों को, उन दलितों को, जिनको नमो शूद्र कहा जाता है, उनके साथ, ईस्ट पाकिस्तान, जो आज बंगलादेश है, वहां अत्याचार होने लगे। उसके बाद वे छोड़कर भागकर आ गए। जिन लोगों को अभी नागरिकता मिली है, 70 से 75 परसेंट वही नमो शूद्र हैं, वही दलित हैं, लेकिन तमाम लोग, जो दलितों की बात करते हैं, जो दलितों के नाम पर पार्टी खाते हैं, हम उनके अग्रणी हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया, दलितों का विरोध किया, उनके अधिकारों का विरोध किया। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : माननीय बृजलाल जी, कन्क्लूड कीजिए।

श्री बृजलाल: समय कम है, इसलिए मैं आज इतना ही कहूंगा।

श्री उपसभापति: आपका बहुत धन्यवाद, आपने समय का पालन किया। डा. सोनल मानसिंह जी।

डा. सोनल मानसिंह (नाम-निर्देशित): उपसभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करती हूं। यह जो किसान आंदोलन पर चर्चा चल रही है, उस पर मेरा एक ही कहना है कि कहीं एक सिनेमा में आया था कि "जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ ऐसी बनी।"

उपसभापति महोदय, यह अच्छा होता कि प्रधान मंत्री मोदी जी की किसानों को लेकर जो अद्भुत बातें हैं, वे अच्छे से सुनी जातीं, तो बात ऐसी के बदले, अच्छे तरीके से आगे बढ़ती। Sir, I am going to speak in English because a lot of my friends like Mr. Siva, who is here, tell me that हिंदी समझ में नहीं आती है, कोई अंग्रेज़ी में क्यों नहीं बोलता है। हिंदी, गुजराती, असमिया, उड़िया, जो भी कहें, लेकिन मैं अंग्रेज़ी में बोलना चाहूंगी। From early years of my life, I heard and imbibed the sutra "मातृ देवो भवः, पितृ देवो भवः, गुरु देवो भवः।" which means revere mother as god, revere father as god and revere *guru* as god. I am happy to see these reflected in significant ways in the speech by the hon. President of India.

India is counted among the great civilizations of ancient times but the only one to sustain its vibrant flow till today -- flow of ideas, values, concepts, arts, sciences and indeed all the streams of knowledge which guided emergence of India as *vishwaguru*. Attacks from foreign lands may have weakened some of them but once again they are in focus now as the foundation of the New Education Policy. Need for such a policy which would collect, combine and coalesce various streams of knowledge was being felt since a long time. NEP seems to be the answer to revitalize and resurrect India's knowledge and cultural traditions which can strengthen our national fabric and ignite creative minds to greater and meaningful endeavour. Culture remains the strongest binding force in India which unfortunately was not considered important element in education in past decades. I am happy to see, Sir, for the first time, under the guidance of Prime Minister, Modi*ji*, the NEP has blended education and culture, as they were meant to be: like flower and its fragrance. For this purpose, NEP has created traditional knowledge system in the context of contemporary times. By dethroning the colonial mindset, it seeks to utilize traditional knowledge and time-tested wisdom also for the purpose of application in research -- this has been lacking somehow -- for which National Research Foundation has been created. The aim is to boost confidence in making inventions and innovations, to boost scientific temper and create base for newer ideas to reflect and meet today's needs.

Sir, at the grassroots level, *shiksha* plus *sanskar,* that is, instilling values through education, is being emphasized through the boost given to *anganwadi* workers, the women, who take care of children's early education. This is very important because thus both the values of "*मातृ देवो भवः*" and "*गुरु देवो भवः*" come together as these ladies fulfil a child's need for care and affection while teaching the

basics of primary education through stories, toys, play, etc., which India has traditionally revered. They are being taught to very, very young kids.

The power of Mother: Mother is called the first guru. And I want -- I am very happy to put these ideas across after all these very heavy debates -- that we must come back to our original values which are peace-giving, loving and caring. Now, the power of Mother: she is called the first guru, whose thoughts get transmitted to the unborn child. Thereafter, from the first moments after birth, it is the Mother who bears the onus of early teaching. Witness the episode, the story of one of the great Rishis of Upanishadic times, Satyakam Jabali. Some of us may recall the film 'Satyakam', which was a take on this fascinating story of a young boy whose entry into a Gurukul was difficult as he is unable to answer questions about his father's name and Gotra. Mother Jabala takes him by the hand and appears in front of Guru Rishi Gautama declaring in ringing tone; "I am Jabala and he is my son Satyakam." And that was enough for the Guru to rise from his seat to offer reverence to मातृशक्ति। No wonder Satyakam learnt the lessons of truth and fearlessness, *nirbhikta,* to become Great Rishi himself. Hence, reposing greater faith in मातृशक्ति for *charitra nirmaan*, character building, which is very, very important, the *aanganwadi maatas* is a step in right direction. I laud it.

Following the broad and all-encompassing vision of Prime Minister Modi*ji*, there is visible influence of women in hitherto male bastions like Coast Guard, Army, even in Air Force as fighter pilots, military police and now even in the COBRA unit of CRPF. It is very significant. I see this, Sir, as personification of the *shiva shakti* concept where the male and female principles come together in a meaningful way. It is indeed amazing to see the surge also in numbers of women entrepreneurs as never before. Mudra Yojana, one of the earliest flagship schemes of Prime Minister Modi*ji*, has helped small-time enterprises by women bringing money, respect and usefulness to women who never dreamt of such a phenomenon in their own lives.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude, Dr. Sonal Mansingh.

DR. SONAL MANSINGH: Absolutely, Sir. This is my last point. Much more in the fields of tourism and culture is envisaged as the web of roads and infrastructure will open up areas and sites hitherto unapproachable.

To fulfil hon. Prime Minister's vision of five-trillion dollar economy, all such initiatives will lead to a generation of job-providers, job-creators and not job-seekers. Sir, hence, I appeal to everyone, let us strive together to create *'Ek Bharat, Shreshtha*

Bharat' towards achieving higher goals for India. May our spirits merge to bring love, peace and friendship.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Dr. Sonal Mansingh. Now, Shri Ram Chander Jangra from the Lok Sabha Gallery.

श्री रामचंद्र जांगड़ा (हरियाणा): धन्यवाद उपसभापति जी। मैं हरियाणा प्रदेश से आया हूं और पहली बार मुझे इस महान सदन में आपने बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण ऊपर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरा विषय भी भारत के श्रमिकों और शिल्पकारों के संबंध में है, लेकिन समय की मर्यादा है। उपसभापति महोदय, आप मुझे बोलने के लिए कितना समय देंगे?

श्री उपसभापति: आपको सात मिनट के लगभग समय मिलेगा।

श्री रामचंद्र जांगडा: सर, ठीक है। मैं सात मिनट में ही अपनी बात पूरी करूंगा। यह विषय बहुत लम्बा है। बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर जी, जो हमारे संविधान के निर्माता थे, उन्होंने एक बात कही थी। संविधान में अगर सब को Right to Equality of Opportunity, अवसर की समानता का अधिकार दे दिया जाए, तो बहुत लोग अपना विकास अपने आप भी कर लेते हैं।

भारत के शिल्पकार और श्रमिक का आपस में एक ऐसा तालमेल है जहां पर शिल्पकार काम करता है, तो वहां पर उसके साथ दो-तीन श्रमिक भी काम करते हैं। मैं भारत के प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी को साधुवाद, धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने शिल्पियों और शिल्पकारों की सुध ली। हम लोगों के हाथों में पत्थरों को तराशते-तराशते छाले पड़ गए थे, उनकी किसी ने परवाह नहीं की, अगर किसी ने परवाह की तो भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने की। उन्होंने 'Make in India' का नारा दिया, 'Vocal for Local' का नारा दिया और भारत के श्रमिकों को, शिल्पकारों को कौशल विकास योजनाओं के साथ जोड़ने की एक स्कीम चलाई, संकल्प लिया। मैं इस बात के लिए अपने प्रदेश के नेतृत्व को भी धन्यवाद देता हूं कि जब भी लोग सत्ता में आए, सब लोगों ने अपने ही बुज़ुर्गों का महिमा मंडन करने के लिए विभिन्न संस्थाओं के नाम के ऊपर नामकरण किया, लेकिन हरियाणा प्रदेश में हमारे मुख्य मंत्री माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पहली बार हिन्दुस्तान में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। उसके अंदर तमाम किस्म की कलाएं, आधुनिक कलाएं, जिनके कारण भारतवर्ष का दुनिया में नाम है, उनको आधुनिक प्रशिक्षण देने के लिए योजनाएं तैयार की गईं।

उपसभापति महोदय, मेरा मार्च में तकरीबन एक साल पूरा हो जाएगा। हम लोग विराजमान थे, हिन्दुस्तान के शिल्पकार कहीं बाहर महात्मा गांधी जी के स्टैच्यू के रूप में, कहीं छत्रपति शिवाजी के स्टैच्यू के रूप में, कहीं बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर के स्टैच्यू के रूप में और फिर अंदर के प्रांगण में आए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी के स्टैच्यू के रूप में राम वी. सुतार की कलाकृतियां मौजूद थीं, लेकिन सदन की कुर्सियों के ऊपर बैठने का अधिकार डा.

रघुनाथ महापात्र जी, कैलाश सोनी जी और रामचंद्र जांगड़ा, जो आपके बीच में बोल रहा है, हमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने और माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने दिया है कि हम भारत के शिल्पकारों और श्रमिकों की आवाज़ इस महान सदन के अंदर सुना सकें, उनकी आवाज़ उठा सकें। मैं इसके लिए उनका जितना धन्यवाद करूं, उतना कम है। चूंकि मेरे पास बोलने के लिए समय कम है, फिर भी मैं एक-दो उदाहरणों का उल्लेख करना चाहूंगा। हमारे देश में अजंता की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं हैं। मैंने तकरीबन पूरा हिन्दुस्तान घूमकर देखा है, लेकिन मैं एक ही बात का उल्लेख करना चाहूंगा। उपसभापति महोदय, अजंता की गुफाओं में पेंटिंग्स बनी हुई हैं और उनका जो कलर है, उसे भारत के शिल्पकारों ने पंसारी की दुकान से या जंगल की जड़ी-बूटियों से कूटकर, छानकर तैयार किया और उस पेंट की चमक 6 हज़ार साल से आज तक वैसी की वैसी बरकरार है। आज कितनी भी बड़ी कम्पनी का, महंगी कम्पनी का कोई भी पेंट खरीद लो, वह 6 महीने बाद खराब हो जाता है। इससे यह विदित होता है कि भारत में ज्ञान और विज्ञान की कोई कमी नहीं थी, बशर्ते कि इन लोगों को अवसर दिया जाता। एक लंबे समय से आज़ादी के बाद - आज़ादी से पहले जो कुछ हुआ, हमें उसका कोई गिला नहीं है, तब भारत के शिल्पकारों के हाथ तक कटवाए गए, भारत के श्रमिकों को बाहर ले जाकर कहीं फ़िजी में, कहीं दूसरे देशों में गुलाम के रूप में, श्रमिक के रूप में रखा गया, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज़ादी के बाद महात्मा गाँधी ने ग्रामीण विकास का जो vision दिया था, उस vision को यहाँ जो भी सत्ताधारी लोग थे, उन्होंने लागू नहीं किया। भारत के शिल्पकार और श्रमिक एक किस्म से नाकारा, बिल्कुल रोजगारविहीन और गरीबी की अवस्था में आ गए और आज भारत का शिल्पकार एवं श्रमिक पिछड़े वर्ग की श्रेणी के अंदर गिना जाता है। मैं प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का, हमारे भाजपा के नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि अगर पहली बार पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्ज़ा दिया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, उसने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्ज़ा दिया है। इनके लिए योजनाएं तैयार की गईं। मैं आज कह सकता हूं कि Make In India, 'vocal for local' और प्रधान मंत्री जी ने जो किया है, वह सराहनीय है। क्योंकि भारत के श्रमिक के पास कोई जायदाद नहीं है, collateral guarantee देने के लिए उसके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि वह बैंक के अंदर गारंटी देकर अपना कोई भी रोजगार विकसित कर सके। उसके पास तो हाथ हैं और हाथों को कोई गिरवी रखता नहीं है। इसलिए प्रधान मंत्री जी ने "मुद्रा योजना" के तहत जो 10 लाख रुपये तक का ऋण without any collateral guarantee के भारत के शिल्पकारों को, श्रमिकों को और आज जो लोग पिछड़े वर्ग में गिने जाते हैं, उनको देने का काम किया है, कानून पास किया है, वह भारत को एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा करेगा क्योंकि दुनिया का इतिहास यह रहा है कि जहाँ कहीं भी, जिस भी राष्ट्र ने तरक्की की है, वहाँ पर जितना शिल्प कला के लोगों को मौका दिया गया है - चाहे वह चीन है, चाहे स्विट्ज़रलैंड है, चाहे जापान है, श्रमिकों और शिल्पियों को जितना भी ..(**व्यवधान**)..

श्री उपसभापति : माननीय रामचंद्र जांगड़ा जी conclude कीजिए।

श्री रामचंद्र जांगड़ा : मैं एक मिनट में conclude कर दूंगा। मैं भारत के प्रधान मंत्री जी के विज़न को, मेरी पार्टी के विज़न को जितना धन्यवाद दूं, उतना कम है। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा। उपसभापति जी, क्योंकि किसान का मुद्दा बीच में आया है, इसलिए मैं सिर्फ एक मिनट लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा।..(**व्यवधान**)..

श्री उपसभापति : आपका समय पूरा हो गया है, आप जल्दी बोलिए। ..(**व्यवधान**)..

श्री रामचंद्र जांगड़ा : मैं सिर्फ एक बात याद दिलवाना चाहता हूं कि मैं हरियाणा में रहता हूं और मैंने वे दिन देखे हैं कि जब किसान को सोसायटी से 10 हज़ार रुपये लोन में मिलते थे, तब उसको 5 हज़ार रुपये नकद दिए जाते थे और उस पर जबरदस्ती 5 हज़ार रुपये की खाद चिपकायी जाती थी कि तुझे रासायनिक खाद उठानी पड़ेगी। उसका ब्याज 24 परसेंट था। अगर उसकी एक किस्त भी टूट जाती थी तो गाँव में सोसायटी की जीप आती थी और किसान को उठाकर तहसील की हवालात में बंद कर दिया करती थी। ..(**व्यवधान**)..

श्री उपसभापति : धन्यवाद जांगड़ा जी।..(**व्यवधान**)..

श्री रामचंद्र जांगड़ा : मेरी बात एक मिनट में पूरी हो जाएगी। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

श्री उपसभापति : अब समय नहीं है। ..(**व्यवधान**)..

श्री रामचंद्र जांगड़ा : मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अपराधी लोगों के लिए तो बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून था, लेकिन किसान को चाहे 40 दिनों तक, जब तक उसकी किस्त नहीं भरी जाती थी, तब तक हवालात में रखा जाता था। अगर इस अपमान से किसी ने उसका पीछा छुड़वाया है, तो जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधान मंत्री बने, केंद्र में पहली बार बीजेपी की सरकार आई, माननीय राजनाथ सिंह जी कृषि मंत्री बने, उस समय किसान के लिए Kisan Credit card की व्यवस्था हुई।..(**व्यवधान**)..

श्री उपसभापति : धन्यवाद। ..(**व्यवधान**)..

श्री रामचंद्र जांगड़ा : उन्होंने किसान का इस ज़िल्लत से पीछा छुड़वाया, इसलिए उन लोगों को याद करना चाहिए। ..(**व्यवधान**)..

श्री उपसभापति : धन्यवाद। ..(**व्यवधान**)..

श्री रामचंद्र जांगड़ा : उपसभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Hon. Members, the Discussion on Motion of Thanks on Mahamahim Rashtrapatiji's Address has concluded and the reply will be on Monday, the 8th February, 2021. माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा संपन्न हो गई है, सोमवार को इस पर जवाब होगा। Now, Special Mention. Shri Rajmani Patel. माननीय राजमणि जी, 2.30 बज गए हैं, सदन का समय पूरा हो गया है, आप अपना Special Mention lay कर दीजिए।

SPECIAL MENTION

Need for giving adequate compensation to farmers whose land is being acquired for Bansagar Irrigation Project

श्री राजमणि पटेल (मध्य प्रदेश): महोदय, जल संसाधन विभाग के लिए किए जा रहे भू-अर्जन के मामले प्रतिकर निर्धारण एवं अवार्ड पारित करने के लिए लम्बे समय से लंबित हैं। भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 की धारा 24(1)(क) के प्रावधान के अनुसार निर्धारण नहीं किया जा रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिनियम, 2013 बनाया गया था, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के किसानों की ज़मीन अधिग्रहण करने पर मुआवज़े का फार्मूला, भूमि का बाज़ार मूल्य एवं सोलेसियम चार गुना देने का प्रावधान किया गया था, जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी शहरी क्षेत्र के फार्मूले पर ज़मीन के बाज़ार मूल्य एवं सोलेसियम को लागू करके ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को सिर्फ दो गुना मुआवज़ा दिया है। राज्य सरकार द्वारा केन्द्र शासन के द्वारा पारित कानून पर अमल नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकारों, विशेषकर मध्य प्रदेश सरकार के इस रवैये के कारण किसानों को भारी नुकसान हो रहा है, जिससे मध्य प्रदेश के किसान आत्महत्या जैसे कठोर कदम उठाने के लिए विवश हो रहे हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि कथित प्रकरण की गंभीरता से जांच करा कर केन्द्र सरकार के अधिनियम, 2013 के तहत किसानों के भू-अर्जन के मुआवज़े का भुगतान शहरी क्षेत्र के फार्मूले के बजाय ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर चार गुना किया जाए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned till 9.00 a.m. on Monday, the 8th February, 2021.

The House then adjourned at thirty minutes past two of the clock till nine of the clock on Monday, the 8th February, 2021.

PUBLISHED UNDER RULE 260 OF RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN THE COUNCIL OF STATES (RAJYA SABHA)